



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026

चैत्र 20, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 5/2026/349/94-2-2026-700(14)-2026

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-219

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति, 2024 के उपबंधानुसार स्तम्भ-2 में वर्णित प्रयोजन हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

स्टाम्प शुल्क छूट से सम्बंधित उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024 का प्रस्तर	विवरण/प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
4.2.2	पात्र जी0सी0सी0 ईकाई को प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि/कार्यालय परिसर/भवन को क्रय करने अथवा पट्टे पर लेने पर	100 प्रतिशत	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खंड(क) के अधीन हस्तान्तरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टे की लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन होगी:-

1-सम्बंधित जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र लिखत में पुष्टि करेगा कि विलेख का निष्पादन उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024 के अधीन हो रहा है तथा उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

2-स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की, अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश अथवा सम्बंधित जिला का जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि पात्र विनिधान अवधि से कम से कम एक वर्ष अधिक की होगी।

3-इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबंध, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त नीति की प्रभावी अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्हीं कारणों से उक्त नीति समाप्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत समझी जायेगी।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 5/2026/349/ XCIV-2-2026-700(14)-2026, dated April 10, 2026 :

No. 5/2026/349/ XCIV-2-2026-700(14)-2026

Dated Lucknow, April 10, 2026

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, the stamp duty, in accordance with the provisions of “The Uttar Pradesh Global Capability Centres Policy, 2024”, chargeable in relation to the instruments shown in column-4, for the purposes described in column-2, to the extent mentioned in column-3 of the Schedule below.

SCHEDULE

Paragraphs of the Uttar Pradesh Global Capability Centres Policy, 2024 relating to stamp duty exemption	Descriptions/Purpose	Extent of Remission	Nature of Instruments
1	2	3	4
Para-4.2.2	To eligible GCC units on purchase/lease of land/ office premises/building for the proposed project	100 percent	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh

The aforesaid remission under this notification shall be subject to the following terms and conditions:—

1. District Magistrate of the concerned district or Deputy Commissioner, District Industries Centre shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the Uttar Pradesh Global Capability Centres Policy, 2024 and shall also sign as a witness for the said purpose.
2. Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty, in favour of the Inspector General, Registration, Uttar Pradesh or the District Magistrate of the concerned district, shall be presented before the registration officer at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should be minimum up to more than one year than the eligible investment period for the GCC units.
3. The provisions mentioned in this notification shall remain in force from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* till the effective period of the aforesaid policy. In case, the said policy comes to end, by any means, the remission granted under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 78 राजपत्र-2026-(154)-599 प्रतियाँ (डीटी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2026-(155)-100+50=150 प्रतियाँ (डीटी0पी0/ऑफसेट)।